सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 560
06/08/2018

‘लोक संवाद’ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

पटना, 06 अगस्त 2018 :– आज **1** अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, गन्ना उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन विभाग से संबंधित मामले पर **07** लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को सुझाव दिया गया।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में दरभंगा के श्री कृष्ण कुमार सुमन यादव, पटना के श्री विनय कुमार, समस्तीपुर के श्री धर्मेश कुमार, जमुई के श्री रजनीश रत्नाकर, कटिहार के श्री राहुल देव, भागलपुर के श्री विशाल कुमार, पटना के श्री अनुज कुमार ने अपने–अपने सुझाव एवं राय मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। प्राप्त सुझाव एवं राय पर संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया। लोगों से प्राप्त सुझाव एवं राय पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, जल संसाधन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, पथ निर्माण मंत्री श्री नंदकिशोर यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री विनोद नारायण झा, उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य मंत्री श्री शैलेश कुमार, गन्ना उद्योग मंत्री श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, पंचायती राज मंत्री श्री कपिलदेव कामत, पर्यटन मंत्री श्री प्रमोद कुमार, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री के0एस0 द्विवेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री अनुपम कुमार सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे।

आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना घृणित, निंदनीय एवं शर्मसार करने वाली है। यह घटना विकृत मानसिकता को दर्शाता है। समाज कल्याण विभाग ने टी0आई0एस0एस0 (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस) की रिपोर्ट के उपरांत कार्रवाई प्रारम्भ की। पुलिस मुश्तैदी से कार्रवाई कर रही थी और विभागीय स्तर पर भी कदम उठाये गये। सदन में उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में जाँच हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी तरह से घटना को गम्भीरता से लेते हुए कार्रवाई प्रारम्भ की। भ्रम का वातावरण पैदा न हो इसलिये सी0बी0आई0 को इस केस की जाँच की जिम्मेवारी सौंपने का निर्णय हमलोगों ने किया। एडवोकेट जेनरल ने माननीय उच्च न्यायालय को कहा कि उच्च न्यायालय की निगरानी में यह जाँच कार्य हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव, डी0जी0पी0, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक में मैंने कहा कि इस बात की पूरी समीक्षा की जाए कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटती है ? तंत्र में कहाँ कमी है। एन0जी0ओ0 के द्वारा बालिका गृह, शेल्टर होम आदि का रख–रखाव किया जाता रहा है। हमलोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अब एन0जी0ओ0 को यह काम नहीं सौंपा जाएगा। ऐसी बालिकाओं/महिलाओं की कानूनी सुरक्षा का दायित्व सरकार का है। हमलोगों ने इन्वेस्टीगेशन के साथ–साथ कार्रवाई को प्राथमिकता दिया। भविष्य में चीजें ठीक से फंक्शन करे, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी तंत्र के द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। यह काम फेज वाइज किया जाएगा, इसके लिए आवास का निर्माण करवाया जाएगा और स्टाफ की बहाली की जाएगी। पूरी जिम्मेवारी के साथ इस काम को किया जाएगा। बिहार पहला ऐसा राज्य है, जिसने स्वतंत्र एजेंसी से सर्वेक्षण कराया और ऐसी घटना की जानकारी सामने आयी। उसके बाद जरूरी कदम उठाये गये हैं। जो कोई भी दोषी होगा, वह नहीं बचेगा चाहे कोई भी हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इसके विरोध में कल कैंडल मार्च निकाल रहे थे और धरने पर बैठे थे, उनके हँसते हुए चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि वे इस घटना के प्रति कितने संवेदनशील हैं। कोई भी बिहारी ऐसा नहीं होगा, जो इस घटना से शर्मिन्दा न हो। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर जिन्हें जो मन में आ रहा है, बोल रहे हैं। इनलोगों की महिलाओं के बारे में कैसी मानसिकता है, यह पूरे देश की महिलायें जानती हैं। सत्ता जब मिली थी तो ये लोग माल बनाने में लगे रहे। देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा न बने इसलिए ये लोग ऐसी अनाप–शनाप हरकत करते रहते हैं। ये खुद ही चार्जशीटेड हैं। सबको बोलने की आजादी है, जिन्हें जो समझ में आता है बोलें, हम इन्हें कोई अहमियत नहीं देते हैं। इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सी0बी0आई0 जाँच कर रही है, कोई भी गड़बड़ करने वाला नहीं बचेगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्यों न शामिल हो। दिए जा रहे जातिगत स्टेटमेंट संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग शुरू से इस तरह की बात करते रहे हैं। ऐसी परम्परा विकसित हो गई है। जो लोग भी ऐसा करते हैं, उनसे हम सहमत नहीं हैं। हम कभी ऐसा नहीं बोले हैं और आगे भी नहीं बोल सकते हैं। हमारा स्वभाव इस तरह का नहीं है। छवि खराब होने से संबंधित प्रश्न का जबाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बिहारवासी इस घटना से शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। हम बिल्कुल कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हमारी छवि बिहार की जनता तय करेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग ने विस्तृत रूप से इस घटना के बैकग्राउण्ड एवं इससे संबंधित उठाये गये कदमों के बारे में पत्रकारों को बताया।

******